



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

NO.P(PC)524/VII - CPC/Allowances

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office  
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch  
चेन्नै/Chennai - 600 003  
दि./ Dated:28-09-2017

आर बी ई सं/RBE No. 121 / 2017

पी बी सी सं/ PBC No.171 / 2017

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /  
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units,  
etc.,

(As per mailing list -'A')

विषय/Sub:Implementation of recommendations of Seventh Central  
Pay Commission accepted by the Government – Flag  
Station Allowance.

\*\*\*\*\*

A copy of Railway Board letter No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-1  
dt. 05-09-2017 (RBE No.121/ 2017) on the above subject is enclosed for  
information, guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम  
Senior Personnel Officer/Rules

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी  
For Principal Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU  
The Genl Secy / AISCSTREA  
The Genl Secy / AIOBCREA  
The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

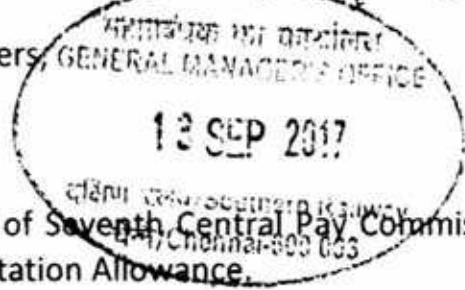
PC-VII No. 57  
RBE No. 121/2017

No. E(P&A)-I-2017/SP-1/Genl-1

New Delhi, dated 15.09.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,  
All Indian Railways & Production Units.

S R, Chennai



Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Flag Station Allowance.

\*\*\*\*\*

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to abolish Flag Station Allowance (Payable to Commercial Staff in charge of Flag Stations where Train passing duties are not involved) as a separate allowance. The eligible employees will now be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance", which shall be governed as under:

- a. Extra Work Allowance will be paid at a uniform rate of 2%(two percent) of the basic pay per month.
  - b. An employee shall receive this allowance for a maximum period of one year, and there should be minimum gap of one year before the same employee is deployed for similar duties again.
  - c. This allowance shall not be combined i.e. if the same employee is performing two or more such duties and is eligible for 2%(two percent) allowance for each add-on, then the total Extra Work Allowance payable will remain capped at 2%(two percent) of basic pay.
2. These orders shall be effective from 1<sup>st</sup> July, 2017.
  3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
  4. Please acknowledge receipt.

*Anil Kumar*  
(Anil Kumar)  
Dy. Director/E(P&A)-I  
Railway Board.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII\*स. 57

आरबीई सं. 121/2017

सं. ई(पी एंड ए)-2017/एसपी-1/जनरल-1

नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

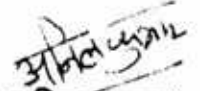
महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - फ्लैग  
स्टेशन भत्ता।

\*\*\*\*\*

भत्तों में संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति फ्लैग स्टेशन भत्ते (उन फ्लैग स्टेशनों जहां ट्रेन पासिंग इयूटियाँ शामिल नहीं होती हैं, के प्रभारी वाणिज्यिक कर्मचारियों को देय है) को अतिरिक्त भत्ते के रूप में समाप्त करते हैं। पात्र कर्मचारी अब नए प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" के तहत शासित होंगे, जिसे निम्नानुसार शासित किया जाएगा:

- क. अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रति माह मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) के समान दर से दिया जाएगा।
  - ख. किसी कर्मचारी को यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, और एक ही कर्मचारी को समान इयूटी पुनः देने में न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।
  - ग. इस भत्ते को संयुक्त न किया जाए यानि यदि एक ही कर्मचारी इस प्रकार की दो या उसे अधिक इयूटी कर रहा है और प्रत्येक इयूटी के लिए 2% (दो प्रतिशत) भत्ते का पात्र है, तो कुल अतिरिक्त कार्य भत्ता देय मूल वेतन का 2% (दो प्रतिशत) तक ही रहेगा।
2. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से जारी होंगे।
  3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
  4. कृपया पावती दें।

  
(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-1  
रेलवे बोर्ड